IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

शोध निष्कर्ष –

इस विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नगरीकरण एक स्वाभाविक, अपरिहार्य और निरंतर चलने वाली आर्थिक प्रक्रिया है, जिसे न तो रोका जा सकता है और न ही रोका जाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को किसी एक सरल श्रेणी में नहीं बाँधा जा सकता, क्योंकि यह वरदान और अभिशाप दोनों रूपों में साथ–साथ उपस्थित है। एक तरफ जहाँ इसने ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिकता, बेहतर आय के साधन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक बाजार से जोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इसने कृषि संकट, श्रम की कमी, पर्यावरण का ह्रास और सांस्कृतिक विस्थापन जैसी जटिल समस्याएँ भी उत्पन्न की हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि नगरीकरण को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देने के बजाय एक सुनियोजित और समावेशी रणनीति के तहत दिशा दी जाए। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा परिकल्पित गाँवों में शहरी स्तर की भौतिक और सामाजिक सुविधाएँ विकसित की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण आबादी का अनावश्यक पलायन रुके। कृषि का आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जब तक ग्रामीण अंचल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं किया जाता, तब तक देश का समग्र और संतुलित विकास अधूरा रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. गोयल, एम. एम. (2015), भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास, साहित्या भवन पब्लिकेशन।
2. सिंह, आर. जे. (2018), नगरीकरण और ग्रामीण समाज, रावत पब्लिकेशंन।
3. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), भारत सरकार की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट।
4. नीति आयोग, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास रणनीतियाँ, शासकीय दस्तावेज।
5. दत्त, रुद्र एवं सुंदरम, के.पी.एम. (2022). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली, एस. चाँद एंड कम्पनी।
6. मिश्र, एस.के. एवं पुरी, वी.के. (2021). भारतीय अर्थव्यवस्था. मुंबई, हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
7. सिंह, योगेन्द्र (2018). भारत में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।
8. श्रीनिवास, एम. एन. (2017). आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
9. देसाई, ए. आर. (2016). भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र. मुंबई, पॉपुलर प्रकाशन।
10. योजना आयोग/नीति आयोग. भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें.
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय. वार्षिक प्रतिवेदन.
12. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. कृषि सांख्यिकी एवं वार्षिक रिपोर्ट.
13. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. भारत की सांख्यिकीय रिपोर्टें

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

शामिल हैं। विश्लेषण पद्धति के अंतर्गत वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। नगरीकरण के विभिन्न आयामों, जैसे आर्थिक विविधीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव, और पर्यावरणीय ह्रास, को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में रखकर परखा गया है। विभिन्न secondary sources से प्राप्त आँकड़ों का तार्किक संश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिससे शोध की गुणवत्ता और अकादमिक कठोरता पूरी तरह सुरक्षित रहे।

व्याख्या –

इस चरण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नगरीकरण के बहुआयामी प्रभावों का विस्तृत और पैराग्राफ–बद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। नगरीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों को कई सकारात्मक दिशाओं में गतिशीलता प्रदान की है, जिनमें गैर–कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन सबसे प्रमुख है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीयक (निर्माण, विनिर्माण) और तृतीयक (परिवहन, व्यापार, संचार और सेवा) क्षेत्रों का व्यापक विस्तार हुआ है। शहरी बाजारों की निरंतर बढ़ती माँग के कारण किसानों ने पारंपरिक खाद्यान्नों के उत्पादन से हटकर नकदी फसलों, बागवानी, पुष्प खेती और डेयरी फार्मिंग को अपनाना शुरू किया है, जिसे कृषि का व्यावसायीकरण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, शहरों की ओर प्रवास करने वाले ग्रामीण श्रमिकों द्वारा अपने गाँवों में भेजे जाने वाले धन ने ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। बुनियादी ढाँचे के मोर्चे पर, पक्की सड़कों के निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग प्रणालियों के प्रसार ने गाँवों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। दूसरी ओर, अनियंत्रित और तीव्र नगरीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समक्ष कई गंभीर संकट और नकारात्मक प्रभाव भी खड़े किए हैं। शहरी विस्तार, रियल एस्टेट बूम और औद्योगिक गलियारों के विकास के कारण उपजाऊ कृषि भूमि का तेजी से अधिग्रहण हो रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति जोत का आकार लगातार घट रहा है और छोटे तथा सीमांत किसान भूमिहीन होने की कगार पर पहुँच रहे हैं। युवाओं के बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन होने के कारण गाँवों में कृषि कार्यों के लिए कुशल और शारीरिक श्रम की भारी कमी हो गई है, जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि खेती का अधिकांश कार्यभार अब महिलाओं पर आ गया है। पर्यावरणीय मोर्चे पर, व्यावसायिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और भूजल के अंधाधुंध दोहन से मिट्टी की उर्वरता और भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली, आपसी भाईचारे और लोक संस्कृति का क्षरण हुआ है तथा व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी संस्कृति ने ग्रामीण समाज के ताने–बाने को कमजोर किया है।

प्रवास इस पूरी प्रक्रिया का एक केंद्रीय और अत्यंत प्रभावशाली घटक है। अस्थायी और स्थायी प्रवास ने जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के दबाव को कुछ हद तक नियंत्रित किया है, वहीं दूसरी ओर गाँवों से मेधावी, ऊर्जावान और कुशल युवाओं के पलायन से स्थानीय नेतृत्व और विकास क्षमता को गहरा आघात पहुँचा है। गाँवों में मुख्य रूप से वृद्ध, महिलाएँ और बच्चे शेष रह गए हैं, जिससे सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय उत्पादकता दोनों प्रभावित हुई हैं। इन सभी अंतर्संबंधों का समग्र अध्ययन यह दर्शाता है कि नगरीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ही समय में अवसर और चुनौती दोनों रूप में कार्य कर रहा है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

अक्सर महिलाओं पर आ जाता है, जिसे कृषि का कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों की देखभाल और गांवों के सामाजिक ताना–बाने के बिखरने जैसी चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं।

नगरीकरण के प्रसार के साथ गांवों और शहरों के बीच की भौतिक दूरियां कम हो रही हैं। सरकार की विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं (जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) और शहरी विस्तार के कारण गांवों में पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट और संचार माध्यम तेजी से पहुंचे हैं। बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क के कारण अब ग्रामीण किसान अपने उत्पादों को सीधे शहरी बाजारों या बिचौलियों के बिना थोक मंडियों तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। परिवहन की सुगमता ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों से गांवों तक उपभोक्ता वस्तुओं की पहुंच ने ग्रामीण उपभोक्ताओं की जीवनशैली और उपभोग पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है।

नगरीकरण के जहां कुछ सकारात्मक आर्थिक परिणाम सामने आए हैं, वहीं इसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के समक्ष गंभीर संकट भी खड़े हुए हैं। अनियोजित शहरी विस्तार के कारण उपजाऊ कृषि भूमि का तेजी से अधिग्रहण हो रहा है, जिससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इसके अलावा, शहरी कचरे का ग्रामीण क्षेत्रों में डंपिंग, भूजल स्तर में भारी गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। पारंपरिक ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, जो स्थानीय कारीगरों की आजीविका का मुख्य साधन हुआ करते थे, शहरी कारखानों में बनने वाली सस्ती और मशीनी वस्तुओं के मुकाबले टिक नहीं पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण कारीगरों का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो रहा है।

शोध का उद्देश्य –

इस शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्म विश्लेषण करना है। सबसे पहले, यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर–कृषि गतिविधियों पर नगरीकरण के प्रभावों का गहन मूल्यांकन करता है ताकि यह समझा जा सके कि पारंपरिक कृषि किस प्रकार आधुनिक व्यावसायिक कृषि में रूपांतरित हो रही है। दूसरा, यह शोध ग्रामीण श्रम बाजार, रोजगार संरचना और प्रवास के पैटर्न का विस्तृत अध्ययन करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तीसरा, यह अध्ययन ग्रामीण बुनियादी ढाँचे, विपणन प्रणालियों, और वित्तीय समावेशन पर नगरीकरण के परिणामों को रेखांकित करता है। चौथा, इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने उत्पन्न पर्यावरणीय संकटों और सामाजिक–सांस्कृतिक बदलावों की पहचान करना है। अंत में, यह शोध ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास के लिए व्यावहारिक समाधान और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिससे ग्रामीण अंचल में सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

शोध पद्धति –

यह शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक डेटा ऐतिहासिक विश्लेषण और गुणात्मक–मात्रात्मक मूल्यांकन पर आधारित है। अध्ययन की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न आधिकारिक स्रोतों और पद्धतियों का उपयोग किया गया है। डेटा के प्रमुख स्रोतों में नीति आयोग की रिपोर्टें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आँकड़े, भारत की जनगणना रिपोर्टें, तथा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के शोध पत्र

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

भारत जैसे विकासशील देशों की आत्मा यदि गांवों में बसती है, तो देश की प्रगति की धड़कनें तेजी से बढ़ते हुए शहरों में सुनाई देती हैं। नगरीकरण समकालीन विश्व और विशेषकर भारतीय समाज की सबसे प्रभावशाली एवं अपरिवर्तनीय सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं में से एक है। ऐतिहासिक रूप से, मानव सभ्यता की शुरुआत गांवों और कृषि से हुई थी, किंतु समय के साथ औद्योगीकरण, तकनीकी क्रांति और बेहतर जीवन स्तर की लालसा ने मानव बस्तियों का स्वरूप बदल दिया।

नगरीकरण केवल गांवों का शहरों में तब्दील होना या शहरों की भौगोलिक सीमा का विस्तार मात्र नहीं है; यह एक संपूर्ण जीवनशैली, आर्थिक ढांचे, सामाजिक मूल्यों और उत्पादन प्रणालियों का रूपांतरण है। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सदियों से कृषि और पारंपरिक कुटीर उद्योगों पर टिकी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज किस प्रकार वैश्विक और शहरी प्रभावों के दौर से गुजर रही है।

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का संबंध एक जटिल प्रक्रिया रहा है। प्रारंभिक दशकों में देश की नीतियां कृषि विकास और ग्रामीण स्वावलंबन पर केंद्रित थीं। श्हरित क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी, जिससे कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हालांकि, समय बीतने के साथ कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया, जोतों का आकार लगातार छोटा होता गया, और पारंपरिक खेती अनिश्चित मानसून तथा बढ़ती लागत के कारण कम लाभकारी होती चली गई।

दूसरी ओर, शहरों में उद्योगों, सेवा क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्रीयकरण ने ग्रामीण आबादी को अपनी ओर आकर्षित किया। आज स्थिति यह है कि शहरों का दायरा गांवों की सीमाओं को छूने लगा है। कई ग्रामीण क्षेत्र अब श्अर्ध–शहरीश क्षेत्रों में बदल चुके हैं, जहां न तो पूरी तरह से ग्रामीण विशेषताएं बची हैं और न ही वे पूर्ण रूप से आधुनिक शहर बन पाए हैं। यह संक्रमणकालीन अवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू को गहराई से प्रभावित कर रही है।

पारंपरिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन रहा है। किंतु नगरीकरण के प्रभाव स्वरूप ग्रामीण श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अब कृषि से दूर होकर गैर–कृषि गतिविधियों की ओर पलायन कर रहा है। शहरों की बढ़ती मांग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों परिवहन, खुदरा व्यापार और असंगठित क्षेत्र के अन्य कार्यों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

इसके साथ ही, शहरी बाजारों की निकटता ने ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों के विविधीकरण के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर अब शहरी बाजारों की मांग को देखते हुए पुष्प उत्पादन बागवानी डेयरी फार्मिंग और कुक्कुट पालन को अपनाया जा रहा है। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार–उन्मुख बना रहा है।

नगरीकरण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पलायन के रूप में देखा जाता है। रोजगार और बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर जाना एक आम प्रवृत्ति बन गई है। यह पलायन दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर जहां यह गांवों में श्रम की कमी का कारण बनता है, वहीं दूसरी ओर शहरों से गांवों में भेजे जाने वाले धन यानी प्रेषण ने ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ाया है।

इस धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों का निर्माण, बच्चों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच संभव हो पाई है। हालांकि, इसके सामाजिक मूल्य भी हैं; युवा पुरुषों के शहरों में बस जाने के कारण गांवों में कृषि का कार्यभार

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नगरीकरण का प्रभाव का एक अध्ययन

ममता जयसवाल
शोधार्थी समाजशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

डॉ. शाहिदा सिद्दीकी
प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश : *नगरीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंतर्संबंध आधुनिक विकास अर्थशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। भारत जैसे विकासशील और कृषि–प्रधान देश में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी निवास करती है, नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने गाँवों के आर्थिक ताने–बाने को गहराई से प्रभावित किया है। यह शोध पत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नगरीकरण के बहुआयामी प्रभावों का विस्तृत और पैराग्राफ–आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, गैर–कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन, प्रवास के पैटर्न, ग्रामीण–शहरी अंतर्संबंध, बुनियादी ढाँचे का विकास, तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक चुनौतियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नगरीकरण ने जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में नगदी फसलों के उत्पादन, बेहतर बाजार पहुँच, प्रेषित धन और आधुनिकीकरण के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि भूमि के संकुचन, श्रम संकट, पारिस्थितिक असंतुलन और पारंपरिक संस्कृति के क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। अंत में, शोध पत्र में संतुलित क्षेत्रीय विकास और सतत ग्रामीण आजीविका के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।*

मुख्य शब्द :– नगरीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विविधीकरण, प्रवासन, ग्रामीण–शहरी अंतर्संबंध, श्रम संकट, सतत विकास आदि।

प्रस्तावना

नगरीकरण मात्र जनसंख्या का गाँवों से शहरों की ओर भौतिक स्थानांतरण नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक संस्थाओं, जीवन शैली, व्यावसायिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों में होने वाला एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। स्वतंत्रता के पश्चात और विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) के बाद भारत में नगरीकरण की गति में अभूतपूर्व तेजी आई है। इस तेज गति ने देश की रीढ़ मानी जाने वाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। पारंपरिक रूप से, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, विशेषकर कृषि और पशुपालन, पर निर्भर रही है। परंतु जैसे–जैसे शहरों का भौगोलिक दायरा बढ़ा है और परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास हुआ है, गाँवों और शहरों के बीच की दूरियाँ कम हुई हैं। यह अंतर्संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान और अभिशाप दोनों रूपों में सामने आया है। एक तरफ जहाँ इसने ग्रामीण क्षेत्रों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इसने पारंपरिक कृषि व्यवस्था के समक्ष गंभीर अस्तित्वगत संकट भी उत्पन्न किए हैं। ऐतिहासिक रूप से, गाँव आत्मनिर्भर इकाइयाँ हुआ करते थे, किंतु नगरीकरण के प्रभाव से अब वे शहरी औद्योगिक केंद्रों पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। इस बदलते परिवेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप, उसकी चुनौतियों और संभावनाओं का समग्र अध्ययन करना आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हो गया ळें